

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5192

जिसका उत्तर 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

12 चैत्र, 1947 (शक)

**भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में असम की भूमिका**

**5192. श्रीमती कमलजीत सहरावत:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में असम की भूमिका से प्राप्त होने वाले मुख्य लाभ कौन-से हैं और इससे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को किस प्रकार सहायता मिलेगी; और
- (ख) असम के डिजिटल परिवर्तन को गति देने और राज्य को प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

(क) सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को स्वीकृति दी है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत, सरकार ने लगभग 1,52,000 करोड़ रुपये के संचयी निवेश के साथ पांच (5) सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) का असम के मोरीगांव में 27,120 करोड़ रुपये के निवेश और 48 मिलियन यूनिट प्रति दिन की उत्पादन क्षमता के साथ आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओसैट) सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है।

(ख) एमईआईटीवाई ने असम के डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और राज्य को प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संबंधी पहलों को वित्त पोषित किया है:

- i. सरकार ने असम में एक संस्थान सहित लगभग 113 प्रतिभागी संस्थानों में वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन में 85,000 उद्योग तैयार कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिए चिप्स टू स्टार्टअप ('सी 2 एस') कार्यक्रम शुरू किया है। अब तक सी2एस कार्यक्रम के अंतर्गत 113 संगठनों में प्रशिक्षण के लिए 43,000 से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, सी2एस कार्यक्रम असम राज्य में 5 संगठनों सहित 300 संगठनों को ईडीए टूल सपोर्ट और नियमित प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
- ii. देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों को आकर्षित करने के लिए सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, असम राज्य में एक ईएमसी की स्थापना को स्वीकृति दी गई है।
- iii. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) के अंतर्गत असम राज्य में एक कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

\*\*\*\*\*